भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-32

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन

***32. श्री डी. राजाः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन विश्व स्तर पर निर्धारित उत्सर्जन मानक से 45 प्रतिशत और चीन के औसत से 14 प्रतिशत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान सेन्टर फॉर साइन्स एंड एन्विरॉवमेन्ट (सीएसई) द्वारा भारतीय ताप-विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन के संबंध में "हीट ऑन पावर ग्रीन रेटिंग ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स" शीर्षक के साथ प्रकाशित रिपोर्ट की तरफ आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्षों का सारांश और उसमें दिए गए सुझावों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 27.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : भारत में कोयले का भण्डार प्रचुर मात्रा में है और भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आधारित उत्पादन महत्वपूर्ण बना रहेगा। देश में ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाइ ऑक्साइड (CO_2) का उत्सर्जन घटिया गुणवत्ता वाले कोयले और भारत में उच्चतर परिवेशी वायु तापमान तथा शीतलक जल तापमान के कारण वैश्विक मानकों की तुलना में अधिक है जिससे कोयले की खपत अधिक होती है।

(ख) और (ग) : विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने अपनी रिपोर्ट "कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की ग्रीन रेटिंग" में अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

I. सुपर क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एससी/यूएससी) संयंत्रों की संस्थापना की गति बढ़ाना।
II. पुराने और अकुशल संयंत्रों को बंद करना।
III. सख्त वायु प्रदूषण मानक लागू करना।
IV. कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में जल और भूमि का प्रयोग इष्टतम करना।

भारत सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार लाने और विद्युत क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पहले ही निम्नलिखित पहलें शुरू कर दी हैं:

I. सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 27,485 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है और 49,925 मेगावाट सुपर क्रिटिकल क्षमता निर्माणाधीन है।

II. पूरी कोयला प्रज्वलित क्षमता अभिवृद्धि 13वीं योजना में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी।

III. अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी) सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी।

IV. कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उच्चतर दक्षता हासिल करने, कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन तथा कोयला खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा बीएचईएल, एनटीपीसी और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) को शामिल करते हुए 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास परियोजना अनुमोदित की गई है।

आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार करने तथा पुरानी एवं अकुशल थर्मल उत्पादन यूनिटों को चरणबद्ध रूप से बंद करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। अब तक कुल 3,115 मेगावाट की क्षमता को पहले ही बंद किया जा चुका है और 2,667 मेगावाट क्षमता को 12वीं योजना के अंत तक बंद किया जाना है।

VI. सरकार ने निर्णय लिया है कि पुराने संयंत्र को दिया गया आश्वासन-पत्र (एलओए)/लिंकेज सार्वजनिक क्षेत्र में नजदीकी सुपर क्रिटिकल क्षमता के नए संयंत्र को स्वतः ही अंतरित हो जाएगा। यदि नए सुपर

कोयला लिंकेज प्रदान किया जाएगा।

2015-16 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के तहत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 100 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति टन (दोगुना) कर दिया गया है।

VIII. देश में समग्र विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना।

IX. भारत सरकार ने निष्पादन, हासिल एवं व्यापार करो (पीएटी) स्कीम की शुरूआत की है जिसमें वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों को दक्षता में सुधार लाने के लिए लक्ष्य दिए जाते हैं।

X. केंद्रीय विदयुत प्राधिकरण ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इष्टतम भूमि, एवं खपत में लाए जाने वाली जल क्रमशः सितंबर, 2010 और जनवरी, 2012 में रिपोर्टें तैयार की हैं जिनका ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा पालन किया जा रहा है।

XI. फ्लाई-ऐश का उपयोग, 1996-97 में 6.64 मिलियन टन (9.63%) था, जो 2013-14 में बढ़कर 99.62 मिलियन टन (57.63%) हो गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-355

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

बन्द पड़े विद्युत संयंत्र

355. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों से देश भर में राज्य-वार कितनी विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं;

(ख) विद्युत परियोजनाओं के बंद होने के क्या कारण रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बंद पड़ी परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ी नौ विद्युत परियोजनाओं का उनके बंद होने के कारण सहित राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	ईंधन	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट	कारण
1.	बिहार	बरौनी टीपीएस	कोयला	210	दोनों यूनिट आधुनिकीकरण एवं नवीकरण की प्रक्रिया

					में हैं
2.	राजस्थान	डीएई (राजस्थान)	नाभिकीय	100	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन
3.	जम्मू एवं कश्मीर	पम्पोर जीपीएस (तरल)	हाई स्पीड डीजल	175	गैर-क्रिफायती प्रचालन
4.	आंध्र प्रदेश	एलवीएस पावर डीजी	डीजल	36.8	गैर-क्रिफायती प्रचालन
5.	पश्चिम बंगाल	चिनाकुरी टीपीएस	कोयला	30	गैर-क्रिफायती प्रचालन
6.		हल्दिया जीटी (तरल)	हाई स्पीड डीजल	40	गैर-क्रिफायती प्रचालन
7.		कस्बा जीटी (तरल)	हाई स्पीड डीजल	40	गैर-क्रिफायती प्रचालन
8.	असम	चंद्रपुर (असम) टीपीएस	बहु ईंधन	60	गैर-क्रिफायती प्रचालन
9.	मणिपुर	लेमखोंग डीजी	डीजल	36	गैर-क्रिफायती प्रचालन

(ग) : उपर्युक्त नौ विद्युत स्टेशनों में से, सात स्टेशन बंद कर दिए गए क्योंकि वे उत्पादन की उच्च लागत के कारण लाभार्थियों द्वारा शिड्यूल नहीं किए जा रहे थे। असम में चंद्रपुर टीपीएस को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में कोयले को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उपयोग करते हुए दोबारा शुरू किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-357

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र को फीडर पृथक्करण हेतु वित्तीय सहायता

357. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात में क्रियान्वित ज्योति ग्राम योजना नामक योजना पर आधारित फीडर पृथक्करण हेतु योजना आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र ने वर्ष 2006 से 2013 के दौरान फीडर पृथक्करण हेतु गॉथन फीडर पृथक्करण योजना (जी.एफ.एस.एस.) नामक योजना का क्रियान्वयन किया था और आर.ई.सी. से ऋण लेकर 2656 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2013 से 2017 के दौरान महाराष्ट्र को पूंजीगत कार्यों के विकास संबंधी स्कीम हेतु योजना-II में 8304.32 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण में फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण, सभी स्तरों पर मीटरिंग के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है।

(ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 2006-2013 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में फीडर पृथक्करण स्कीम अर्थात् गॉथन फीडर पृथक्करण के लिए 2123.44 करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋणों को मंजूरी दी थी और अब तक इन ऋणों के लिए 1899.12 करोड़ रुपये का वितरण आरईसी द्वारा प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ) : महाराष्ट्र सहित सभी राज्य कार्य के क्षेत्र और उसके दिशा-निर्देशों के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र हैं तथा डीडीयूजीजेवाई के प्रचालनीकरण हेतु नोडल एजेंसी की उनकी प्राथमिकता के अनुसार अपने आवश्यक मूल्यांकन दस्तावेज तथा डीपीआर प्रस्तुत कर सकते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-358

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

अधूरी परियोजनाएं

358. श्रीमती प्लव ठाकुरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत के प्रत्येक क्षेत्र में आज की तिथि के अनुसार अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं का तथा इनके अपूर्ण रहने के कारणों का हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उन परियोजनाओं को पूरा करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक परियोजना को पूरा करने हेतु निर्धरित समय सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : हिमाचल प्रदेश सहित निर्माणाधीन ताप (कोयला/गैस आधारित) तथा जल विद्युत परियोजनाओं का विलंब के कारणों और चालू होने की अनुसूची सहित क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 27.04.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 358 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	देरी के कारण
केंद्रीय क्षेत्र						
बोंगाईगांव टीपीपी	*असम*	यू-1	250	जन.-11	जून-15	निरंतर बंद, भारी वर्षा और धीमा सिविल कार्य। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वर्ष 2011-12 के दौरान हिंसा तथा स्थल से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य रूक गया। सिविल ठेकेदारों द्वारा खराब निष्पादन के कारण सिविल कार्य प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनका ठेका निरस्त कर दिया गया। शेष सिविलऔर संरचनात्मक कार्य 29.09.2014 को एनबीसीसी को दे दिए गए।
		यू-2	250	मई-11	16-17	
		यू-3	250	सितं.-11	16-17	
बाढ़ एसटीपीपी-I	*बिहार*	यू-1	660	अक्तू.-13	17-18	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के संविदात्मक विवाद के कारण विलंब। वित्तीय दिक्कतों के कारण मैसर्स टीपीई द्वारा बायलर सामग्री एवं खरीदी जाने वाली मदों (बीओआई) की आपूर्ति में विलंब। मैसर्स टीपीई ने 10/13 को कार्य बंद कर दिया। एनटीपीसी द्वारा 14.01.2015 को मैसर्स टीपीई का करार समाप्त कर दिया। मैसर्स पावर मशीन द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और मंद प्रगति।
		यू-2	660	अप्रैल-14	17-18	
		यू-3	660	अक्तू.-14	18-19	
मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपैं.	*बिहार*	यू-4	195	जन.-13	फर.-16	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य अवार्ड करने में विलंब। सिविल कार्यों को पूरा करने में विलंब। भूमि अधिग्रहण में विलंब। कच्चा जल लाइन के लिए राइट ऑफ एप्रोच (आरओए) की उपलब्धता में विलंब। सीएचपी, एएचपी एवं स्विचयार्ड की तैयारी में विलंब।
नबीनगर टीपीपी	*बिहार*	यू-1	250	मई-13	दिसं.-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी मैसर्स ईआरए द्वारा धीमी गति से कार्य जिससे निर्माण एजेंसियों को सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब हुआ। भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति। गांववासियों द्वारा आन्दोलन। लोगों द्वारा मुआवजे को ग्रहण करने की अनिच्छा के कारण भूमि के कुछ टुकड़ो का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। सीएचपी वेंडर (टैक्प्रो) द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई।
		यू-2	250	सितं.-13	दिसं.-16	
		यू-3	250	जन.-14	जून-16	
		यू-4	250	मई-14	जून-17	
लारा टीपीएस	*छत्तीसगढ़*	यू-1	800	नवं.-16	नवं.-16	–
		यू-2	800	मई-17	मई-17	–
न्यू नबीनगर टीपीपी	*बिहार*	यू-1	660	जन.-17	जून-17	शेष भूमि का अधिग्रहण तथा वासक्षेत्र स्वामियों का स्थान परिवर्तन, जो अभी भी परियोजना क्षेत्र में रह रहे हैं।
		यू-2	660	जुला.-17	सितं.-17	
		यू-3	660	जन.-18	जन.-18	
बोकारो टीपीएस "क" एक्सपैं.	*झारखण्ड*	यू-1	500	दिसं.-11	मार्च-16	भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। स्विचयार्ड के स्थान परिवर्तन तथा भूमिगत सुविधाओं को हटाने में विलंब के कारण भेल को फ्रंट्स सौंपने में विलंब। मूल्य अंतर मुद्दों का समाधान

						करने में विलंब। सीएचपी तथा एनडीसीटी की तैयारी।
नार्थ करनपुरा टीपीपी	*झारखण्ड*	यू-1	660	फर.-18	फर.-18	–
		यू-2	660	अग.-18	अग.-18	–
		यू-3	660	फर.-19	फर.-19	–
कुडगी एसटीपीपी फेज-I	*कर्नाटक*	यू-1	800	दिसं.-15	जुला.-16	एसजी सिविल कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। टीजी निर्माण की शुरुआत में विलंब। 03/14 में एनजीटी आदेश के कारण कार्य बंदी। जनशक्ति के निष्क्रमण से 07/14 में आक्रोश और हिंसा तथा कार्य का बंद होना।
		यू-2	800	जून-16	दिसं.-16	
		यू-3	800	दिसं.-16	मई-17	
मौदा एसटीपीपी-II	*महाराष्ट्र*	यू-1	660	मार्च-16	अक्तू.-16	मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी (आईवीआरसीएल) द्वारा कार्य की मंद प्रगति। आपूर्ति में विलंब तथा बॉयलर के स्थापना कार्यों में मंद प्रगति।
		यू-2	660	सितं.-16	अप्रैल-17	
सोलापुर एसटीपीपी	*महाराष्ट्र*	यू-1	660	मई-16	मई-17	बीजीआर द्वारा एसजी आपूर्ति में विलंब। कच्चा पानी पाइपलाइन के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) में विलंब। मैसर्स आईवीआरसीएल द्वारा सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
		यू-2	660	नवं.-16	नवं.-17	
विंध्यांचल टीपीपी फेज-V	*मध्य प्रदेश*	यू-13	500	अग.-15	अक्तू.-15	बीओपी आदेश में विलंब। बॉयलर सामग्री के इरेक्शन में विलंब।
गदरवारा एसटीपीपी	*मध्य प्रदेश*	यू-1	800	मार्च-17	जून-17	शेष भूमि अधिग्रहण और शेष बीओपी के ऑर्डर में विलंब। ग्रामीणों द्वारा आंदोलन के कारण सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
		यू-2	800	सितं.-17	नवं.-17	
दारलीपल्ली एसटीपीपी	*ओडिशा*	यू-1	800	फर.-18	फर.-18	–
		यू-2	800	जून-18	जून-18	–
तूतीकोरिन जेवी	*तमिलनाडु*	यू-2	500	अग.-12	जुला.-15	मुख्य संयंत्र उपस्करों के बुनियादी डिजाइन में परिवर्तन। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। जनशक्ति की कमी। पेय जल की उपलब्धता और विद्युत आपूर्ति में विलंब। वैधानिक स्वीकृतियां (वन्य जीव, वन स्वीकृति इत्यादि) प्राप्त होने में विलंब।
मोनार्चक सीसीपीपी	*त्रिपुरा*	एसटी	39.7	जुला.-13	जुला.-15	सिविल कार्य संविदा के अवार्ड में और भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। भारी वर्षा। गैस पाइपलाइन और गैस गैदरिंग स्टेशन तैयारी में विलंब। डीएम प्लांट, पीटी, सीटी, सीडब्लयू सिस्टम आदि की तैयारी में विलंब।
उंचाहार स्टे- IV	*उत्तर प्रदेश*	यू-6	500	दिसं.-16	नवं.-17	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य पैकेज और बीओपी अवार्ड करने में विलंब।
मेजा एसटीपीपी	*उत्तर प्रदेश*	यू-1	660	जून-16	मई-17	मैसर्स बीजीआर द्वारा बॉयलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
		यू-2	660	दिसं.-16	नवं.-17	
टांडा टीपीपी	*उत्तर प्रदेश*	यू-1	660	मई-18	मई-18	–
		यू-2	660	नवं.-18	नवं.-18	–
रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	*पश्चिम बंगाल*	यू-2	600	मई-11	दिसं.-15	यूनिट-I के चालू होने में विलंब। जल और रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। आरआईएल द्वारा मुख्य संयंत्र उपस्करों के इरेक्शन में विलंब। कानून एवं व्यवस्था की समस्या। स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार कार्यबंदी। बॉटम रिंग हेडर को बदलना। बॉयलर इंसुलेशन तथा एनडीसीटी-I की क्षति के कारण विलंब।
रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II	*पश्चिम बंगाल*	यू-3	660	अग.-17	13वीं योजना	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों को शुरू करने में विलंब।
		यू-4	660	जन.-18	13वीं योजना	
राज्य क्षेत्र						–

रायलसीमा टीपीपी स्टे –III	*आंध्र प्रदेश*	यू-6	600	जुला.-14	दिसं.-16	सिविल एवं भूमि अधिग्रहण कार्य को प्रांरभ करने और पूरा करने में विलंब। बीओपी कार्यों में विलंब।
नामरूप सीसीजीटी	*असम*	जीटी	70	सितं.-11	मार्च-16	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल कार्यो की मंद प्रगति, सिविल ठेकेदारों की सेवा समाप्ति। खराब मृदा तथा भारी वर्षा। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी। एनबीपीएल आदेश की समाप्ति। सिविल तथा इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन एजेंसी के रि-अवार्ड में विलंब।
		एसटी	30	जन.-12	जून-16	
बरौनी टीपीएस एस्टें.	*बिहार*	यू-1	250	मई-14	फर.-16	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब। सीटी, सीडब्ल्यू प्रणाली आदि की तैयारी में विलंब तथा इंटेक पम्प हाउस, कच्चा पानी लाइन आदि के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण में विलंब।
		यू-2	250	जुला.-14	जून-16	
मारवा टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-2	500	जुला.-12	जुला.-15	आरम्भिक विलंब चिमनी अवार्ड किए जाने में परिवर्तन के कारण हुआ था। बोओपी (सीएचपी, एएचपी और 400 केवी स्विचयार्ड आदि) की तैयारी में विलंब और कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, सामग्री आदि की चोरी। मैसर्स बीजीआर द्वारा जनशक्ति की कमी।
सिक्का टीपीपी एक्सटें.	*गुजरात*	यू-4	250	जन.-14	दिसं.-15	सिविल फ्रण्ट्स की तैयारी तथा बीओपी आदेश देने में विलंब। बॉयलर एण्ड टीजी की स्थापना में धीमी प्रगति। बीओपी विशेष रूप से सीएचपी तथा एएचपी में धीमी प्रगति। बीटीजी स्थापना एजेंसी में परिवर्तन। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	*गुजरात*	यू-1	250	अक्तू.-13	अग.-15	सिविल कार्य में विलंब तथा गैर-क्रमिक आपूर्ति। बीओपी में धीमी प्रगति। एएचपी तथा लिग्नाइट हैंडलिंग संयंत्र की तैयारी में विलंब। कच्चा पानी की उपलब्धता में विलंब।
		यू-2	250	दिसं.-13	नवं.-15	
बेल्लारी टीपीएस	*कर्नाटक*	यू-3	700	अग.-14	नवं.-15	मुख्य संयंत्र और बीओपी के लिए सिविल संविदा अवार्ड करने में विलंब। एएचपी विक्रेता और भेल के बीच विवाद। एलपी रोटर की आपूर्ति में विलंब।
येरमारस टीपीपी	*कर्नाटक*	यू-1	800	अप्रैल-14	दिसं.-15	मार्सलिंग यार्ड के ओरियंटेशन में परिवर्तन, प्लॉट योजना में परिवर्तन और विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त मृदा जांच और तृतीय पक्ष के निरीक्षण के कारण मृदा जांच की पुनरावृत्ति।
		यू-2	800	अक्तू.-14	अप्रैल-16	
चंद्रपुर टीपीएस	*महाराष्ट्र*	यू-9	500	सितं.-12	अग.-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब और मुख्य संयंत्र उपकरण आपूर्ति में विलंब। बीओपी की तैयारी में विलंब और भारी वर्षा।
कोराड़ी टीपीपी एक्सपें.	*महाराष्ट्र*	यू-9	660	जून-14	जुला.-15	सिविल कार्यों में विलंब। भारी वर्षा के कारण कार्य की प्रगति में विलंब। वित्तीय संकट के कारण मैसर्स लैंको इंफ्राटेक द्वारा बीओपी (कूलिंग टावर, एएचपी, सीएचपी इत्यादि) की तैयारी में विलंब।
		यू-10	660	दिसं.-14	फर.-16	
पार्ली टीपीपी एक्सपें.	*महाराष्ट्र*	यू-8	250	जन.-12	अक्तू.-15	बीओपी आदेश देने में विलंब। बीटीजी आपूर्ति में विलंब। रेखाचित्रों के अनुमोदन में विलंब। धीमा निर्माण कार्य। बीओपी में धीमी प्रगति। मैसर्स सुनील हाइटेक के साथ वाणिज्यिक विवाद के कारण बीओपी की मंद प्रगति।
कालीसिंध टीपीएस	*राजस्थान*	यू-2	600	मार्च-12	मई-15	बंकरों और कोयला मिलों की तैयारी में विलंब तथा मैसर्स बीजीआर द्वारा शेष सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
छाबड़ा एसटीपीपी	राजस्थान	यू-5	660	जून-16	अप्रैल-17	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
		यू-6	660	सितं.-16	दिसं.-18	
सूरतगढ़ एसटीपीपी	राजस्थान	यू-7	660	सितं.-16	अप्रैल-17	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
		यू-8	660	दिसं.-16	जुला.-17	

काकातिया टीपीपी एक्सटें.	*तेलंगाना*	यू-1	600	जुला.-12	नवं.-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब तथा बीओपी ठेकेदार संघ लीडर के बदलने के कारण विलंब। भेल द्वारा स्थापना एजेंसी के अवार्ड में विलंब। टैक्प्रो द्वारा सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब। कच्चा पानी जलाशय के लिए स्थान को अंतिम रूप में देने में विलंब।
सिंगरैनी टीपीपी	*तेलंगाना*	यू-1	600	फर.-15	जन.-16	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब।
		यू-2	600	जून-15	मार्च-16	
अनपरा-डी	*उत्तर प्रदेश*	यू- 6	500	मार्च-11	जून-15	बीओपी के लिए ऑर्डर देने में विलंब। फायर फाइटिंग कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति। भेल द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति परिनियोजन। एएचपी, सीडब्ल्यू एवं एफओ प्रणाली में कार्य की धीमी प्रगति।
		यू-7	500	जून-11	सितं.-15	
सागरदीघी टीपीपी-II	*पश्चिम बंगाल*	यू-3	500	जुला.-14	सितं.-15	निर्माण और बीटीजी सामग्री की आपूर्ति की धीमी प्रगति। इलेक्ट्रिकल इरेक्शन कार्य के लिए ऑर्डर देने में विलंब। ठेका समाप्त करने तथा पुनः अवार्ड देने के कारण एएचपी की तैयारी में विलंब।
		यू-4	500	अक्तू.-14	मार्च-16	
निजी क्षेत्र						
भावनापडु टीपीपी फेज-I	*आंध्र प्रदेश*	यू-1	660	अक्तू.-13	मई-17	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण कार्य लंबे समय तक रूका रहा। कार्य पुनः प्रारंभ करने के पश्चात दो चक्रवातों के कारण कार्य प्रभावित हुआ। राज्य विभाजन के विरूद्ध आन्दोलन। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कार्य की मंद प्रगति।
		यू-2	660	मार्च-14	अक्तू.-17	
एनसीसी टीपीपी	*आंध्र प्रदेश*	यू-1	660	मार्च-15	जून-16	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा मंद प्रगति के कारण विलंब। वित्तीय कठिनाई के कारण सामग्री आपूर्ति एवं इरेक्शन में विलंब।
		यू-2	660	जून-15	नवं.-16	
पैनमपुरम टीपीपी	*आंध्र प्रदेश*	यू-2	660	अग.-14	जुला.-15	टीजीटी सिविल कार्य की शुरुआत में विलंब। भूमि संबंधी मामले के कारण नींव डिजाइन में परिवर्तन के कारण विलंब।
थम्मिनापट्टनाम टीपीपी स्टेज -II	*आंध्र प्रदेश*	यू-3	350	मई-12	अग.-16	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कार्य लंबे समय तक बंद रहा।
		यू-4	350	अग.-12	नवं.-16	
विजग टीपीपी	*आंध्र प्रदेश*	यू-1	520	जून-13	सितं.-15	विद्युत शुरू करने के लिए पारेषण लाइन के तैयार होने में विलंब। सिविल कार्यों, समुद्री जल इंटेक और आउट फॉल प्रणाली सीएचपी इत्यादि की प्रगति में विलंब रेलवे लाइन तैयार करने में विलंब। तूफान के कारण हुई क्षति के कारण विलंब
		यू-2	520	सितं.-13	दिसं.-15	
जस इंफ्रा. टीपीएस	बिहार	यू-1	660	अग.-14	-	साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	660	दिसं.-14	-	
		यू-3	660	अप्रैल-15	-	
		यू-4	660	अग.-15	-	
अकलतारा टीपीपी (नैयारा)	*छत्तीसगढ़*	यू-3	600	दिसं.-12	दिसं.-15	जनशक्ति की कमी, ग्राम वासियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन। निधि संबंधी बाधाओं के कारण सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
		यू-4	600	अप्रैल-13	मार्च-17	
		यू-5	600	अग.-13	दिसं.-17	
		यू-6	600	दिसं.-13	मार्च-18	
बाल्को टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	300	फर.-11	जून-15	चिमनी का ढहना। राज्य सरकार द्वारा प्रचालन के लिए सहमति देने में विलंब
		यू-2	300	नवं.-10	सितं.-15	

बंदाखार टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	300	दिसं.-12	मई-15	सिविल कार्यों को शुरू करने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित हुआ। सीएचपी / एएचपी तैयार करने में विलंब और जेनरेटर स्टार्टर की समस्या।
बिंजकोट टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	300	अग.-13	दिसं.-15	सिविल कार्यों में विलंब। बॉयलर ड्रम की आपूर्ति में विलंब। एसटीजी निर्माण एजेंसियों में परिवर्तन के कारण बॉयलर एवं टीजी के लिए निर्माण कार्य बंद होने के कारण विलंब।
		यू-2	300	नवं.-13	मार्च-16	सिविल कार्यों की शुरुआत में विलंब। प्रेशर पार्टों के निर्माण की धीमी प्रगति।
		यू-3	300	फर.-14	-	कार्य अभी शुरू किया जाना है।
		यू-4	300	मई-14	-	कार्य अभी शुरू किया जाना है।
लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	*छत्तीसगढ़*	यू-3	660	जन.-13	-	जल प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण वर्तमान में साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-4	660	मार्च-13	-	
रायखेड़ा टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-2	685	जन.-14	जुला.-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कभी-कभी विभिन्न कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई।
सिंघीतराई टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	600	जून-14	मार्च-16	भूमि अधिग्रहण में विलंब। बॉयलर एवं टीजी निर्माण की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्याओं के कारण विलंब।
		यू-2	600	सितं.-14	अग.-16	
टीआरएन एनर्जी टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	300	दिसं.-13	अप्रैल-16	सिविल कार्यों की शुरुआत में विलंब। बॉयलर एवं टीजी निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति। जनशक्ति की कमी।
		यू-2	300	अप्रैल-14	मार्च-17	
उंचपिंडा टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	360	मई-12	जून-15	ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य प्रभावित हुआ। साइट पर कार्य की धीमी प्रगति। बीओपी तैयार करने में विलंब। विद्युत स्टार्ट अप तैयार करने में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण विलंब।
		यू-2	360	नवं.-12	अग.-15	
		यू-3	360	फर.-13	अक्तू.-15	
		यू-4	360	जुला.-13	मार्च-16	
सलोरा टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-2	135	सितं.-11	जुला.-15	यूनिट-I को चालू करने में विलंब। ग्रामीणों द्वारा साइट पर विरोध। बीटीजी और सीएचपी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। चालू करने के कार्यों में बीटीजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सहयोग न करना।
वीसा टीपीपी	*छत्तीसगढ़*	यू-1	600	अग.-13	17-18	एएचपी, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, एसी एवं वातायन प्रणाली, एलटी/एचटी स्विचगियर, केबल, एयर कंप्रेशर, एलटी ट्रांसफार्मर, स्टेशन, जीटी एवं यूनिट ट्रांसफार्मरके लिए आदेश अब तक नहीं दिए गए हैं। वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य रुका हुआ है।
मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	*झारखण्ड*	यू-1	270	मई-12	-	कानून व व्यवस्था की समस्या। बीटीजी उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। वन स्वीकृति के कारण पारेषण लाइन तैयार करने में विलंब। नवम्बर, 2012 से वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रोक दिया गया है।
		यू-2	270	जून-12	-	
मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	*झारखण्ड*	यू-3	270	फर.-13	-	कानून व व्यवस्था की समस्या और बीटीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। साइट पर वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य रोक दिया गया है।
		यू-4	270	मार्च-13	-	
तोरी टीपीपी	*झारखण्ड*	यू-1	600	जून-13	17-18	कानून व व्यवस्था की समस्या। सिविल कार्य की शुरुआत में विलंब एवं कार्य की धीमी प्रगति। यूनिट-II के लिए एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। पूर्व में आवंटित कोयला ब्लॉकों के रद्द होने के बाद कार्य रोक दिया गया।
		यू-2	600	जन.-15	17-18	
अमरावती टीपीपी फेज-II	*महाराष्ट्र*	यू-1	270	जुला.-14	-	वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	270	सितं.-14	-	

		यू-3	270	नवं.-14	-	
		यू-4	270	जन.-15	-	
		यू-5	270	मार्च-15	-	
लेंको विदर्भा टीपीपी	*महाराष्ट्र*	यू-1	660	जन.-14	-	वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	660	मई-14	-	
नासिक टीपीपी फेज-I	*महाराष्ट्र*	यू-2	270	अप्रैल-12	सितं.-15	रेलवे साइडिंग तैयार करने में विलंब। बीटीजी सामग्री की क्रमरहित आपूर्ति एवं सिविल फ्रंट की तैयारी। भेल के साथ भुगतान का मामला। मिलों, एचएफओ, सीएचपी एवं एएचपी, डक्टिंग इंसुलेशन आदि की तैयारी।
		यू-3	270	जून-12	17-18	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीटीजी सामग्री स्वीकार न करना। वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-4	270	अग.-12	17-18	
		यू-5	270	अक्तू.-12	17-18	
नासिक टीपीपी फेज-II	*महाराष्ट्र*	यू-1	270	अप्रैल-13	-	वित्तीय समस्याओं के कारण इस स्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। इसे 13वीं योजना में ले जाया जा सकता है।
		यू-2	270	जून-13	-	
		यू-3	270	अग.-13	-	
		यू-4	270	अक्तू.-13	-	
		यू-5	270	दिसं.-13	-	
अनूपपुर टीपीपी फेज -I	*मध्य प्रदेश*	यू-2	600	अग.-13	फर.-16	सिविल कार्यों शुरू करने में विलंब एवं धीमी प्रगति। बॉयलर ड्रम की आपूर्ति में विलंब। बॉयलर एवं ईएसपी के इंसुलेशन की तैयारी।
महान टीपीपी	*मध्य प्रदेश*	यू-2	600	सितं.-11	17-18	कोयला ब्लॉक/कोयला लिंकेज उपलब्ध न होने के कारण अत्यधिक धीमी प्रगति।
गोरजी टीपीपी	*मध्य प्रदेश*	यू-1	660	जून-13	-	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए अब तक आदेश नहीं दिया गया है।
सिओनी टीपीपी फेज-I	*मध्य प्रदेश*	यू-1	600	मार्च-13	16-17	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब। चिमनी की तैयारी। वित्तीय समस्या के कारण बॉयलर और टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वर्तमान में साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
निवारी टीपीपी	*मध्य प्रदेश*	यू-2	45	मई-14	15-16	साइट पर कार्य बंद होने के कारण विलंब।
इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	*ओडिशा*	यू-1	350	सितं.-11	जून-15	भारी बारिश के कारण विलंब। विद्युत स्टार्ट अप के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।
		यू-2	350	दिसं.-11	नवं.-15	
केवीके नीलांचल टीपीपी	*ओडिशा*	यू-1	350	दिसं.-11	17-18	आरंभ में चिमनी स्वीकृति और कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण विलंब हुआ। माननीय उच्च न्यायालय, ओडीशा द्वारा स्टे के कारण कार्य रोक दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने 20.05.2014 को कार्य शुरू करने का आदेश दिया है। भूधारकों द्वारा परियोजना की संशोधित लागत के अनुमोदन में विलंब।
		यू-2	350	जन.-12	17-18	
		यू-3	350	मार्च-12	18-19	
लेंको बाबंध टीपीपी	*ओडिशा*	यू-1	660	अप्रैल-13	-	भूमि अधिग्रहण में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।
		यू-2	660	अग.-13	-	
मली ब्राह्मणी टीपीपी	*ओडिशा*	यू-1	525	दिसं.-12	16-17	भूमि अधिग्रहण में विलंब और टीजी हॉल संरचनाओं की आपूर्ति में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण धीमी प्रगति।
		यू-2	525	फर.-13	17-18	

गोइंदवाल साहिब टीपीपी	*पंजाब*	यू-1	270	अप्रैल-13	15-16	सीएचपी एवं एएचपी की तैयारी में विलब। रेलवे लाइन की तैयारी में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण साइट पर कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।
		यू-2	270	अक्तू.-13	16-17	
तलवंडी साबो टीपीपी	*पंजाब*	यू-2	660	जन.-13	मई-15	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब। जनशक्ति की कमी के कारण एएचपी, चिमनी, मिल, कूलिंग टॉवर की तैयारी में विलंब। भारी बारिश के कारण बॉयलर इंसुलेशन कार्य में विलंब हुआ।
		यू-3	660	मई-13	अग.-15	
मेलामरूथुर टीपीपी	*तमिलनाडु*	यू-2	600	मार्च-12	सितं.-15	मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। जनशक्ति की कमी एवं स्विच यार्ड तथा डीएन संयंत्र की तैयारी के कारण विलंब। रेत की आपूर्ति के लिए और भूमिगत जल के उपयोग हेतु नीति में परिवर्तन। बैंकरों द्वारा अतिरिक्त ऋण के संवितरण में विलंब।
तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	*तमिलनाडु*	यू-1	660	मई-12	सितं.-17	सिविल कार्यों की देर से शुरुआत और धीमी प्रगति तथा स्थल पर बॉयलर संरचनात्मक सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
प्रयागराज (बारा) टीपीपी	*उत्तर प्रदेश*	यू-1	660	फर.-14	अक्तू.-15	बीटीजी आपूर्ति में विलंब। विद्युत स्टार्ट अप के लिए रॉ वॉटर पाइप लाइन की तैयारी और पारेषण लाइन की तैयारी। वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कार्य की प्रगति में विलंब हुआ।
		यू-2	660	जुला.-14	जन.-16	
		यू-3	660	दिसं.-14	मई-16	
ललितपुर टीपीपी	*उत्तर प्रदेश*	यू-1	660	अक्तू.-14	जून-15	भारी बारिश के कारण विलंब, टीजी इरेक्शन शुरू करने में विलंब, बॉयलर इंसुलेशन और ईंधन तेल प्रणाली की तैयारी इत्यादी में विलंब। वित्तीय समस्याएं।
		यू-2	660	फर.-15	दिसं.-15	
		यू-3	660	जून-15	सितं.-16	

एचटी- हाइड्रो टेस्ट
बीएलयू- बॉयलर लाइट अप
टीजी- टरबाइन जेनरेटर
एडब्ल्यूपीएच- ऐश वाटर पम्प होम
बीओपी- बैलेंस ऑफ प्लांट
एसबीओ- स्टीम ब्लोइंग ऑफ
सीएचपी- कोल हैंडलिंग प्लांट
ईपीसी - इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन

आरओ/डीएम- रिवर्स ओसमोसिस/डेमिनरालाइज
जीटी जी- गैस टरबाइन जेनरेटर
एसटीजी- स्टीम टरबाइन जेनरेटर
ईडीटीए- एथिलीन डेमियेन टैरा एसिटिक एसिड
आरडब्ल्यूपीएच- रॉ वाटर पम्प होम
एचआरएसजी- हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर
बीटीजी- बॉयलर टरबाइन जेनरेटर
एनजीटी – नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 27.04.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 358 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निर्माणाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	विलंब के कारण
	जम्मू व कश्मीर						
1	किशनगंगा	केंद्रीय	1 2 3	110 110 110	2015-16 2015-16 2015-16	2016-17 2016-17 2016-17	➢ परियोजना के टर्नकी निष्पादन के लिए न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा लगाई जाने वाली बोली की कीमत अधिक होने को ध्यान में रखते हुए संशोधित सीसीईए को अनुमोदित 14.01.2009 को किया गया। ➢ मार्च, 2011 में भारी बारिश। ➢ एचआरटी-टीबीएम भाग में केविटी। ➢ एक्सेस टनल में खराब भूविज्ञान। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा कार्य रोक दिया गया। ➢ अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता प्रक्रियाओं के कारण बांध कार्य प्रभावित हुआ। ➢ रोजगार आर एंड आर संबंधी मामले।
2	बगलीहार-II	राज्य	1 2 3	150 150 150	2015-16 2015-16 2015-16	2015-16 2015-16 2016-17	➢ संविदा की लागत को अंतिम रूप देने में विलंब। ➢ कठिन ईएंडएम कार्य।
3	रत्ले	निजी	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	
	हिमाचल प्रदेश						
4	कोल डैम	केंद्रीय	4	200	2009-10	2015-16	➢ बांध की मिट्टी/भराई बांध गैलरियों की ग्राउटिंग, स्पिलवे की कंक्रीटिंग की धीमी प्रगति। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ इस्पात के प्रापण में विलंब। ➢ कमजोर भूविज्ञान, क्ले कोर की नींव में रिसाव के कारण राइट बैंक का विफल होना। ➢ जलाशय भराव के दौरान डाइवर्जन सुरंग में रिसाव ➢ ईएल 574 से ऊपर जलाशय भराई के लिए 44 हैक्टेयर भूमि के लिए एफसीए स्वीकृति।
5	पारबती-II	केंद्रीय	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	➢ माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने स्टोन क्रशर प्रचालन पर रोक लगाई। ➢ संशोधित वन स्वीकृति में विलंब। ➢ नवंबर, 2006 में टीबीएम फेस में पानी और गाद के भारी मात्रा में प्रवेश करने के कारण टीबीएम को अत्यधिक क्षति हुई। ➢ फरवरी, 07 में पावर हाउस क्षेत्र में स्लाइड। ➢ अगस्त, 2011 में अचानक बाढ़। ➢ केविटी ट्रीटमेंट के कारण जीवा नाला कार्य प्रभावित

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	विलंब के कारण
							हुआ। ➢ संविदा संबंधी मामले ।
6	कशांग-I	राज्य	1	65	2013-14	2015-16	➢ सिविल और ईएंडएम कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➢ 2013 में मानसून में भारी बारिश के दौरान पहुंच सड़कों का बह जाना।
7	कशांग-II व III	राज्य	1 2	65 65	2013-14 2013-14	2016-17 2016-17	➢ स्थानीय मुद्दे। लीपा ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध के कारण कार्य शुरू नहीं हो सके। मामला न्यायाधीन है। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
8	उहल-III	राज्य	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07	2016-17 2016-17 2016-17	➢ कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ संविदाकर्ता द्वारा धीमी प्रगति और कार्य न करने के कारण मई, 2008 और जुलाई, 2010 के दौरान एचआरटी निर्माण के लिए दो बार संविदा रद्द की गई। ➢ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति।
9	स्वारा कुड्डू	राज्य	1 2 3	37 37 37	2010-11 2010-11 2010-11	2016-17 2016-17 2016-17	➢ एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। ➢ सिविल एवं ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ एचआरटी लाइनिंग की धीमी प्रगति। ➢ संविदा संबंधी मामले।
10	सैंज	राज्य	1 2	50 50	2014-15 2014-15	2016-17 2016-17	➢ एचआरटी और बैराज कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ स्थानीय मुद्दे।
11	शोंगटोंग करछम	राज्य	1 2 3	150 150 150	2017-18	2017-18	➢ आर्मी एम्न्यूनिशन डिपो का स्थानांतरण।
12	टिडोंग-I	निजी	1 2	50 50	2013-14 2013-14	2016-17 2016-17	➢ परियोजना प्रभावित पंचायतों द्वारा एनओसी में विलंब। सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को स्थगित करना।
13	टंगनु रोमई-I	निजी	1 2	22 22	2014-15 2014-15	2016-17 2016-17	➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ खराब भौगोलिक परिस्थिति। ➢ कठिन क्षेत्र। ➢ जलवायु परिस्थितियां एवं पहुंच।
14	सोरांग	निजी	1 2	50 50	2012-13 2012-13	2015-16 2015-16	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ कठिन क्षेत्र। ➢ मौसमी स्थिति और पहुंच। ➢ वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पैनस्टॉक क्रैक्स/लीकेज।
15	बजोली होली	निजी	1 2 3	60 60 60	2017-18 2017-18 2017-18	2017-18 2017-18 2017-18	
16	चंजू-I	निजी	1 2 3	12 12 12	2017-18 2017-18 2017-18	2017-18 2017-18 2017-18	
	पंजाब						
17	शाहपुर कंडी	राज्य	1 2 3 4 5	33 33 33 33 33	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	विलंब के कारण
			6	33	2017-18	2017-18	
			7	8	2017-18	2017-18	
	उत्तराखण्ड						
18	तपोवन विष्णुगाड	केंद्रीय	1	130	2012-13	2017-18	➢ सिविल ठेकेदारों द्वारा सुरंग बोरिंग मशीन के प्रापण/तैनाती में विलंब। ➢ खराब पत्थर स्ट्राटा के कारण पावर हाउस में धीमी प्रगति। ➢ एचआरटी में खराब भूविज्ञान और टीबीएम पर पत्थर गिरने के कारण अत्यधिक जल का प्रवेश। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➢ बैराज और एचआरटी के लिए सिविल संविदाओं की समाप्ति
			2	130	2012-13	2017-18	
			3	130	2012-13	2017-18	
			4	130	2012-13	2017-18	
19	लता तपोवन	केंद्रीय	1	57	2017-18	2018-19	➢ जून, 2013 के दौरान अचानक बाढ़ (उत्तराखंड त्रासदी)। ➢ बैराज क्षेत्र में स्थानीय मामले/कार्य प्रारंभ न होना। ➢ माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्माण कार्य जारी रखने पर रोक लगाई।
			2	57	2017-18	2018-19	
			3	57	2017-18	2018-19	
20	टिहरी पीएसएस	केंद्रीय	1	250	2011-12	2018-19	➢ ई एंड एम कार्यों की विशेषज्ञता वाली प्रकृति। ➢ एल-1 कीमत बोली के रूप में आरसीई का अनुमोदन लागत अनुमानों से अधिक था।आरसीई अक्टूबर, 2010 में अनुमोदित किया गया। ➢ मुकदमेबाजी। ➢ खराब भूविज्ञान। ➢ असेना क्वारी में स्थानीय विरोध। ➢ मक डिस्पोजल क्षेत्र में विरोध। ➢ संविदाकर्ता द्वारा खराब तैयारी। ➢ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण मशीन हॉल के ले आऊट की समीक्षा। ➢ असेना क्वारी में खनन कार्यों के लिए अनुमति।
			2	250	2011-12	2018-19	
			3	250	2011-12	2018-19	
			4	250	2011-12	2018-19	
21	विष्णुगाड पीपलकोटि	केंद्रीय	1	111	2018-19	2018-19	➢ सीसीईए अनुमोदन अगस्त, 2008 में प्राप्त परंतु वन स्वीकृति/वन भूमि के परिवर्तन के कारण कार्य अवार्ड नहीं किया जा सका। वन भूमि जनवरी, 14 में अधिगृहीत की गई तथा बाद में जनवरी,2014 में कार्य अवार्ड किया गया। ➢ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध।
			2	111	2018-19	2018-19	
			3	111	2018-19	2018-19	
			4	111	2018-19	2018-19	
22	श्रीनगर	निजी	1	82.5	2005-06	2015-16	➢ वित्तीय बंदी। ➢ डैम कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ एमओईएफ ने कार्य बंद करने के लिए 30.05.2011 से अगस्त, 2013 तक नोटिस जारी किया। ➢ स्थानीय मुद्दे। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़। ➢ वाटर कंडक्टर सिस्टम के भराव के दौरान पावर चैनल में लीकेज।
			2	82.5	2005-06	2015-16	
			3	82.5	2005-06	2015-16	
			4	82.5	2005-06	2015-16	
23	सिंगोली भटवारी	निजी	1	33	2014-15	2017-18	➢ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध। ➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
			2	33	2014-15	2017-18	
			3	33	2014-15	2017-18	
24	फाटा ब्यूंग	निजी	1	38	2013-14	2017-18	➢ जून, 2013 में अचानक बाढ़।
			2	38	2013-14	2017-18	
	मध्य प्रदेश						

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	विलंब के कारण
25	महेश्वर	निजी	1	40	2001-02	2016-17	➢ आरएंडआर मुद्दे। ➢ विकासकर्ता के साथ नकदी प्रवाह की समस्या।
			2	40	2001-02	2016-17	
			3	40	2001-02	2016-17	
			4	40	2001-02	2016-17	
			5	40	2001-02	2016-17	
			6	40	2001-02	2016-17	
			7	40	2001-02	2016-17	
			8	40	2001-02	2016-17	
			9	40	2001-02	2016-17	
			10	40	2001-02	2016-17	
	महाराष्ट्र						
26	कोयना लेफ्ट बैंक पावर हाउस	राज्य	1	40	2017-18	2017-18	
			2	40	2017-18	2017-18	
	तेलंगाना						
27	लोअर जुराला	राज्य	1	40	2011-13	2015-16	➢ ईएंडएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। भूमि अधिग्रहण की समस्या। ➢ 2009, 2010, 2012 और 2013 में अप्रत्याशित बाढ़। ➢ लगातार बंद। ➢ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध। ➢ ग्रामीणों द्वारा 23.04.2011 से 30.11.2012 तक राईट फ्लैंक बांध कंक्रीटिंग रोक दी गई। ➢ एचएम कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ पानी की कम उपलब्धता के कारण 2013-14 में यूनिट-I और II चालू नहीं की जा सकी। ➢ प्रियदर्शिनी जुराला से बाढ़ के पानी के छोड़े जाने के कारण 30.07.2014 को विद्युत गृह का डूब जाना।
			2	40	2011-13	2015-16	
			3	40	2011-13	2015-16	
			4	40	2011-13	2015-16	
			5	40	2011-13	2016-17	
			6	40	2011-13	2016-17	
28	पुलीचिंताला	राज्य	1	30	2009-11	2016-17	➢ ईएंडएम कार्य। ➢ अक्तूबर, 2009 और सितंबर, 2011 में अप्रत्याशित बाढ़। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ विद्युत गृह कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ संविदा संबंधी मामले।
			2	30	2009-11	2016-17	
			3	30	2009-11	2016-17	
			4	30	2009-11	2016-17	
	आंध्र प्रदेश						
29	नागार्जुन सागर टेल पूल डैम	राज्य	1	25	2008-09	2015-16	➢ 2009, 2011 और 2013 के दौरान लगातार बाढ़ के कारण बांध की धीमी प्रगति। ➢ एचएम कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। ➢ डैम कार्यों में संविदा संबंधी मामले। ➢ जल की अनुपलब्धता।
			2	25	2008-09	2015-16	
	केरल	राज्य					
30	पल्लीवसल	राज्य	1	30	2010-11	2016-17	➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ भूमि अधिग्रहण में विलंब। ➢ एचआरटी के लिए अद्रिट के संरेखण में परिवर्तन। ➢ एचआरटी में खराब भौगोलिक स्ट्राटा। ➢ भारी मानसून।
			2	30	2010-11	2016-17	
31	थोटियार	राज्य	1	30	2012-13	2016-17	➢ भूमि अधिग्रहण मुद्दे। ➢ स्थानीय लोगों द्वारा 2010 से 2012 तक वायर और अप्रोच चैनल के कार्य रोक दिए गए।
			2	10	2012-13	2016-17	

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	विलंब के कारण
							➢ न्यायालय द्वारा 12.12.2012 से अप्रैल, 2013 तक कार्य रोक दिया गया।
	पश्चिम बंगाल						
32	तीस्ता लो डैम-IV	केंद्रीय	1 2 3 4	40 40 40 40	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10	2015-16 2015-16 2016-17 2016-17	➢ वन स्वीकृति में विलंब। ➢ जुलाई, 2007, मई, 2009 और जुलाई, 2010 में अचानक बाढ़। ➢ गोरखा जन मुक्ति आंदोलन/बंद। ➢ सिविल संविदाकार(मैसर्स एचसीसी) की धन संबंधी समस्या, मार्च, 2013 से नवंबर, 2014 तक सिविल कार्य पूरी तरह से रूका हुआ है।
	सिक्किम						
33	तीस्ता स्टेज-III	निजी	1 2 3 4 5 6	200 200 200 200 200 200	2011-12 2011-12 2011-12 2011-12 2011-12 2011-12	2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17	➢ वन स्वीकृति में विलंब। ➢ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य प्रभावित हुए। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं। ➢ प्रेशर शॉफ्ट कार्यों में विलंब। ➢ विद्युत निकासी व्यवस्था में विलंब।
34	तीस्ता स्टेज-VI	निजी	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ भूमि अधिग्रहण। ➢ संविदा संबंधी मामले। ➢ विकासकर्ता के साथ निधि संबंधी बाधाएं।
35	रंगित-IV एचई प्रोजेक्ट	निजी	1 2 3	40 40 40	2012-13 2012-13 2012-13	2017-18 2017-18 2017-18	➢ खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी और सर्ज शॉफ्ट कार्यों की धीमी प्रगति। ➢ सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्य बाधित हुए। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
36	जोरथांग लूप	निजी	1 2	28 28	2012-13 2012-13	2015-16 2015-16	➢ खराब भौगोलिक स्थिति। ➢ पारेषण लाइन के लिए वन स्वीकृति। ➢ एचआरटी कार्यों में विलंब।
37	भास्मे	निजी	1 2	25.5 25.5	2012-13 2012-13	2017-18 2017-18	➢ वन स्वीकृति। ➢ विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।
38	ताशिडिंग	निजी	1 2	48.5 48.5	2017-18 2017-18	2017-18 2017-18	
39	दिक्चू	निजी	1 2 3	32 32 32	2017-18 2017-18 2017-18	2017-18 2017-18 2017-18	
40	रंगित-II	निजी	1 2	33 33	2017-18 2017-18	2017-18 2017-18	
41	रोंगनीचू	निजी	1 2	48 48	2017-18 2017-18	2017-18 2017-18	
42	पनन	निजी	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	
	मेघालय						
43	न्यू उमतरू	राज्य	1 2	20 20	2011-12 2011-12	2016-17 2016-17	➢ कार्यों के अवार्ड में विलंब। ➢ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
	अरुणाचल प्रदेश						
44	पारे	केंद्रीय	1	55	2013-14	2015-16	➢ कानून-व्यवस्था की समस्या।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का नवीनतम समय	विलंब के कारण
			2	55	2013-14	2015-16	➢ ठेकेदार के पास संसाधनों की कमी। ➢ कमजोर भूविज्ञान। ➢ सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। ➢ खराब पहुंच सड़क। ➢ बांध की कंक्रीटिंग एवं संबद्ध एचएम कार्य।
45	कामेंग	केंद्रीय	1 2 3 4	150 150 150 150	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10	2016-17 2016-17 2016-17 2016-17	➢ बांध पैरामीटरों में परिवर्तन। ➢ खराब भूविज्ञान, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी में धीमी प्रगति। ➢ अक्टूबर, 2008 और सितंबर, 2012 में अचानक बाढ़। ➢ एचआरटी में जल का प्रवेश। ➢ खराब पहुंच सड़क। ➢ संविदात्मक मामले। ➢ मिलावे की कमी। ➢ राज्य सरकार से खदान के लिए स्वीकृति।
46	सुबानसिरी लोअर	केंद्रीय	1 2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250 250	2009-10 2009-10 2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 2010-11	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	➢ अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। ➢ जनवरी, 2008 में पावर हाउस में स्लोप विफलता। ➢ रंगानदी नदी पर पुल क्षति। ➢ सर्ज शॉफ्ट्स से सर्ज टनल्स के डिजाइन में परिवर्तन। ➢ परियोजना के निर्माण के विरोध में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा घोषित आंदोलन के कारण कार्यबंदी। दिनांक 16.12.2011 से कार्य रूक गया। ➢ डी/एस प्रभाव अध्ययनों का मामला।
47	गोंगरी	निजी	1 2	72 72	2017-18 2017-18	2017-18 2017-18	
	मिजोरम						
48	तुरियल	केंद्रीय	1 2	30 30	2006-07 2006-07	2016-17 2016-17	➢ जून, 2004 से स्थानीय अशांति के कारण समय से पहले कार्यो का निलंबन। ➢ 14.01.2011 को कार्य पुनः प्रारंभ। ➢ खराब पहुंच सड़क। ➢ ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त एकत्रीकरण। ➢ पावर हाउस में स्लोप का असफल होना।

*****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-359

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों
का वित्तीय पुनर्गठन

359. श्रीमती रेणुका चौधरीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन हेतु एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की उनकी वितरण इकाइयों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में मदद करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्य वितरण कंपनियों के प्रचालन, निष्पादन और वित्तीय स्थिति में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण भारी हानियां हुई थीं और अरक्षणीय कर्ज इकट्ठा हो गया था, सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पुनर्गठन के लिए एक योजना तैयार की गई एवं दिनांक 05.10.2012 को अधिसूचित की गई थी, ताकि उनमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जा सके। इस स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा एक परिवर्तनीय वित्तीय तंत्र के माध्यम से सहायता प्राप्त करते हुए राज्य डिस्कॉमों तथा राज्य सरकार के कर्जों के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय निहित हैं। इस योजना की उपलब्धता अवधि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीः-

- **राज्य सरकार 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉमों की बकाया अल्पकालिक देयताओं (एसटीएल) के 50% को अपने अधिकार में लेगी। इसे पहले डिस्कॉमों द्वारा प्रतिभागी ऋणदाताओं को जारी किए जाने वाले बाण्ड में परिवर्तित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार की विधिवत् गारण्टी प्राप्त होगी। राज्य सरकार इसके बाद अपने एफआरबीएम स्पेस के अनुरूप विशेष प्रतिभूतियां जारी करते हुए**

अगले 2-5 वर्षों में डिस्कॉमों की इस देयता को अपने अधिकार में ले लेगी। राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियां जारी करते हुए अधिकार में लेने की तिथि तक ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान में सहायता प्रदान करेगी।

- शेष 50% अल्पकालिक देयताओं को ऋणदाताओं द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान पर स्थगन सहित सर्वोत्तम संभव शर्तों पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
- इस योजना में आमूल-चूल परिवर्तन योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर समितियों द्वारा द्विस्तरीय निगरानी तंत्र निहित था।
- केंद्र सरकार आरएपीडीआरपी (अब आईपीडीएस में शामिल) के अंतर्गत निर्दिष्ट हानि ट्रेजेक्ट्री से आगे त्वरित एटी एण्ड सी हानि कम करते हुए बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के बराबर अनुदान देते हुए प्रोत्साहन प्रदान करेगी और योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई देयताओं पर राज्य सरकार द्वारा 25% मूल के पुनर्भुगतान की पूंजीगत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्कीम में राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉमों की दीर्घकालिक वित्तीय एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध ढंग से किए जाने वाले तत्काल/निरंतर एवं अन्य उपाय निहित थे। इन उपायों में वित्तीय पुनर्गठन, प्रशुल्क निर्धारण एवं राजस्व वसूली, सब्सिडी, मीटरिंग, लेखा-परीक्षा एवं लेखा तथा निगरानी शामिल हैं।

(ग) : सरकार ने अपनी वितरण यूटिलिटियों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीमें भी शुरू की हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-360

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

पीजीसीआईएल द्वारा वेबसाइटों/पोर्टलों पर विज्ञापन

360. श्री सालिम अन्सारीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा विभिन्न वेबसाइटों/पोर्टलों पर विज्ञापन के संबंध में क्या नीति है;

(ख) किन-किन वेबसाइटों/पोर्टलों को पीजीसीआईएल से विज्ञापन सहयोग मिला है और विज्ञापन के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या इनमें से कुछ वेबसाइट पोर्टल गोपनीय दस्तावेजों के लीक किए जाने से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस के जांच के दायरे में हैं; और

(घ) क्या पी जी सी आई एल, दोषी वेबसाइटों/पोर्टलों को विज्ञापन सहायता देने के संदर्भ में पीजीसीआईएल के अधिकारियों की भूमिका की जांच सीवीसी/सीवीओ के माध्यम से कराएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) में वेबसाइटों/पोर्टलों पर विज्ञापन देने के लिए कोई ऐसी नीति नहीं है। तथापि, पीजीसीआईएल बजट की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए और प्रचार की आवश्यकता/कंपनी की कारपोरेट छवि निर्माण के हित के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी करता है।

(ख): पावरग्रिड द्वारा वेबसाइटों/पोर्टलों पर जारी किए गए विज्ञापनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

क्रम संख्या	वेबसाइटों/पोर्टलों के नाम	विज्ञापनों के लिए भुगतान की राशि (रूपए में)
1	www.sarkaritel.com	4,50,000
2	www.thesynergyonline.com	50,000
3	www.psuconnect.in	50,000
4	www.whispersinthecorridors.com	3,00,000
5	www.newpowergame.com	2,40,000

(ग) और (घ): पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के पास उन वेबसाइटों/पोर्टलों के ब्यौरे नहीं हैं जिनकी दिल्ली पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। यदि पीजीसीआईएल की जानकारी में ऐसी कोई सूचना आती है तो वे आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-361

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

असम में विद्युत की कमी

361. श्रीमती नाजनीन फारुखः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि असम में विद्युत की भारी किल्लत के चलते इस राज्य के कई गांवों में विद्युत सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान, असम में ऊर्जा उपलब्धता, 8,555 मिलियन यूनिट की ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में 7,926 मिलियन यूनिट (एमयू) थी जो ऊर्जा में 629 मिलियन यूनिट की कमी दर्शाती है। 12वीं योजना के दौरान, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के अंतर्गत 1009 गैर-विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) और 10259 गहन विद्युतीकृत गांवों (आईईवी) को शामिल किया गया है।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थित गांवों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है।

(ग) : विद्युत की कमी को दूर करने के लिए राज्य की सहायता करने हेतु, केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से 777 मेगावाट विद्युत का आबंटन किया है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सर्वाधिक आबंटन है। केंद्र सरकार ने असम सहित राज्यों को अपने प्रत्याशित मांग आपूर्ति परिदृश्य के अनुसार, अपनी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है। 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों को चालू करने से असम को 847 मेगावाट का संभावित लाभ प्राप्त होगा। राज्य क्षेत्र में 100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की भी संभावना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-362

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा पकड़ी बरवाडीह कोयला ब्लॉक का विकास किया जाना

362. श्री ए. विलियम रबि बर्नार्डः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि एनटीपीसी लिमिटेड उच्चतम न्यायालय में दिए गए अपने आश्वासन के अनुरूप झारखण्ड स्थित पकड़ी बरवाडीह कोयला ब्लॉक को मार्च, 2015 के अन्त तक विकसित करने तथा संचालित करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस कोयला ब्लॉक के विकास की क्या स्थिति है; और

(घ) इस कोयला ब्लॉक को विकसित करने में एनटीपीसी द्वारा क्या उपलब्धि अर्जित की जानी है और इस ब्लॉक को विकसित करने के लिए किन-किन ठेकेदारों को रखा गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी खदान ब्लॉक स्थल पर कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या के कारण मार्च, 2015 तक पकरी बारवाडीह कोयला ब्लॉक से उत्पादन शुरू नहीं कर सका।

(ग) और (घ) : एनटीपीसी ने खनन प्रचालन आरंभ करने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक अनुमोदन/अनुमतियां/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। इससे 2015-2016 के दौरान उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। ब्लॉक के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख संविदाकारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है:

क्रम सं.	कार्य	संविदाकार
1.	कोल हेंडलिंग प्लांट (सीएचपी)	मैसर्स टैक्प्रो
2.	पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कालोनी	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. (एनबीसीसी)
3.	रेलवे साइडिंग	रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विस (आरआईटीईएस)
4.	बनदाग-हजारीबाग रेलवे लिंक	पूर्व मध्य रेलवे
5.	220 केवी पारेषण लाइन	मैसर्स जेनस इंफ्रा. लि.
6.	11 केवी कंस्ट्रक्शन पावर	झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (जेएसईबी)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-363

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग

363. श्री तपन कुमार सेनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना-कितना रहा है;

(ख) विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए /उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत अनुबंध में दी गई है।

(ख): विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत में असमानता सामान्यतया राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनसंख्या में व्यापक विभिन्नता और उपभोक्ता के मिश्रण के कारण है।

(ग): विद्युत उत्पादन में वृद्धि प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के उपायों में से एक है और दूसरा उपाय विद्युत आपूर्ति की संबद्धता और विश्वसनीयता बढ़ाना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 88,537 मेगावाट है। क्षमता अभिवृद्धि के इस स्तर से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग की पूर्ति होने की संभावना है। सरकार ने राज्यों को, उनके प्रत्याशित मांग-आपूर्ति परिदृश्य के अनुरूप, उनकी मांग को पूरा करने के लिए विद्युत के प्रापण हेतु व्यवस्था करने की सलाह दी है। भारत सरकार द्वारा पहुँच बढ़ाने और वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और वितरण कंपनियों के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) शुरू की गई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 27.04.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 363 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

(केडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	2012-13	2013-14*	2014-15*
चंडीगढ़	1168	1133	1052
दिल्ली	1613	1446	1561
हरियाणा	1722	1773	1909
हिमाचल प्रदेश	1380	1348	1336
जम्मू व कश्मीर	1043	1066	1169
पंजाब	1761	1810	1858
राजस्थान	982	1011	1123
उत्तर प्रदेश	450	472	502
उत्तराखण्ड	1297	1285	1358
छत्तीसगढ़	1495	1601	1719
गुजरात	1796	1973	2105
मध्य प्रदेश	753	764	813
महाराष्ट्र	1239	1183	1257
दमन एवं दीव	7927	8003	6960
दादर नागर हवेली	14341	14515	13769
गोवा	2045	2198	1803
आंध्र प्रदेश	1135	1196	1040
तेलंगाना			1356
कर्नाटक	1129	1179	1211
केरल	630	645	672
तमिलनाडु	1226	1544	1616
पुडुचेरी	2136	1692	1655
लक्षद्वीप	592	665	657
बिहार	145	160	203
झारखण्ड	847	810	835
ओडिशा	1209	1349	1419
पश्चिम बंगाल	594	609	647
सिक्किम	862	700	685
अंडमान-निकोबार	559	368	361
अरुणाचल प्रदेश	719	503	525
असम	240	280	314
मणिपुर	353	266	295
मेघालय	690	684	704
मिजोरम	469	445	449
नागालैंड	268	259	311
त्रिपुरा	296	331	303
अखिल भारत	914	957	1010

* अनंतिम

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-364

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत उत्पादन में सुधार से संबंधित योजना

364. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में ताप विद्युत उत्पादन में सुधार लाए जाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) सरकार विद्युत क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कब तक पूरा किए जाने की आशा रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): 2014-15 के दौरान अखिल भारतीय ताप विद्युत उत्पादन 2013-14 के दौरान 792.47 बीयू की तुलना में 10.83% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए 878.32 बीयू रही। देश में ताप विद्युत उत्पादन में और अधिक सुधार करने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः-

I. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए कोयला ब्लाकों का नीलामी/आबंटन के माध्यम से पुनःआबंटन। इससे देश में ताप विद्युत उत्पादन में सुधार होगा।

II. जो विद्युत परियोजनाएं गैस की कम आपूर्ति के कारण प्रभावित हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम स्वीकृत की है जिसमें रिवर्स-ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए स्ट्रेंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा साथ ही साथ, लक्ष्य पीएलएफ तक घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को आयातित स्पॉट आरएलएनजी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। स्कीम में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

III. क्षमता अभिवृद्धि का अनुपूरण करने के लिए तक मितव्ययी विकल्प के रूप में, पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों के नवीकरण, आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) तथा जीवन-विस्तार (एलई) पर विचार किया जाता है। 12वीं योजना के दौरान जीवन विस्तार कार्यों के लिए 12066 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली कुल 70 थर्मल उत्पादन यूनिटों और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 17301 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 65 थर्मल उत्पादन यूनिटों को चिन्हित किया जा चुका है।

IV. उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अंतर/अंतःराज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

V. मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, ताप, नाभिकीय तथा गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण।

(ख): आपूर्ति एवं मांग के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए, 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट की अतिरिक्त् क्षमता (जिसमें नवीकरणीय स्रोतों से नियोजित 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि शामिल नहीं है) को जोड़े जाने की योजना बनाई गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-365

जिसका उत्तर 27 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

तेलंगाना को चौबीसों घण्टे बिजली की आपूर्ति

365. श्री देवेंदर गौड टी.:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आगामी दो वर्षों में तेलंगाना को चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ख) क्या इस संबंध में राज्य से परामर्श किया गया है क्योंकि पारेषण के लिए तार बिछाना विद्युत उत्पादन के जैसा ही महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत का वितरण राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राज्य नीति के अनुसार सभी परिवारों/घरों औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा कृषि उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों को तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है।

तेलंगाना के लिए सभी दस्तावेजों हेतु राज्य विशिष्ट 24x7 घंटे विद्युत की योजना तैयार की जा रही है और इसमें तेलंगाना राज्य में 24x7 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने की कार्ययोजना शामिल की जाएगी।

(ख) : केंद्रीय दल, जिसमें विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से सदस्य शामिल हैं, विद्युत से संबंधित सभी मामलों जिनमें पारेषण पर्याप्तता और उपर्युक्त लक्ष्य का कार्यान्वयन करने के लिए संबद्ध लाइनों के मामले पर चर्चा करने के लिए 30 मार्च, 2015 को तेलंगाना राज्य सरकार के साथ परामर्श किया था।

****